रजिस्ट्री सं० डी०(डी)—73

REGISTERED NO. D-(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 50] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 10, 1977 (अग्रहायण 19, 1899)

No. 50] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 10, 1977 (AGRAHAYANA 19, 1899)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	653
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	1663
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	1323
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . .	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें . .	—
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . .	3363
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . .	4141
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	559
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	5609
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	987
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	189
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं . . .	2267
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	197

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	653
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1663
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	1323
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations.	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	3363
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	4141
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	559
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..	5609
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	987
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	189
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2267
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	197

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिवत नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 नवम्बर 1977

संकल्प

सं० 48012/7/76-सी० ए० 1—भारत सरकार ने अपने संकल्प सं० 38-1/73-सी० ए० 1, दिनांक 5 सितम्बर, 1973 द्वारा गठित भारतीय बागवानी विकास परिषद को 1 जुलाई, 1977 से पुनर्गठित करने का निर्णय किया है। परिषद का पुनर्गठन निम्नलिखित रूप से किया जायेगा :—

1. अध्यक्ष	एक गैर-सरकारी व्यक्ति जिसे भारत सरकार नामजद करेगी।
2. उपाध्यक्ष	अपर सचिव, भारत सरकार, कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग)।
3 सदस्य	
(क) संसद सदस्य	तीन संसद सदस्य जिन्हें संसद कार्य विभाग नामजद करेगा।
(ख) राज्य सरकारों के प्रतिनिधि	निम्नलिखित राज्य सरकारों के कृषि। बागवानी विभागों का एक-एक प्रतिनिधि, जिन्हें संबंधित राज्य सरकारें नामजद करेंगी।
	(1) असम
	(2) आंध्र प्रदेश
	(3) हिमाचल प्रदेश
	(4) हरियाणा
	(5) जम्मू तथा काश्मीर
	(6) कर्नाटक
	(7) महाराष्ट्र
	(8) मध्य प्रदेश
	(9) मेघालय
	(10) उड़ीसा
	(11) पंजाब
	(12) तमिलनाडु
	(13) उत्तर प्रदेश
(ग) केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि	(1) योजना आयोग का एक प्रतिनिधि
	(2) वाणिज्य मंत्रालय का एक प्रतिनिधि
	(3) खाद्य विभाग का एक प्रतिनिधि
	(4) भारत सरकार के कृषि आयुक्त अथवा उनका नामित व्यक्ति।
	(5) महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली अथवा उनका नामित व्यक्ति।
	(6) निदेशक, बागवानी अनुसंधान संस्थान 255, अपर पैले आर्चर्डस, बंगलौर।
	(7) निदेशक, केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर अथवा उनका नामित व्यक्ति।
(घ) उत्पादकों के प्रतिनिधि	(क) निम्नलिखित राज्यों से उत्पादकों के एक-एक प्रतिनिधि, जिन्हें सम्बन्धित राज्य सरकारें नामजद करेंगी।
	(1) असम
	(2) आंध्र प्रदेश
	(3) गुजरात
	(4) हरियाणा
	(5) हिमाचल
	(6) जम्मू तथा काश्मीर
	(7) कर्नाटक
	(8) महाराष्ट्र
	(9) मेघालय
	(10) पंजाब
	(11) राजस्थान
	(12) तमिलनाडु
	(13) उत्तर प्रदेश
	(14) पश्चिम बंगाल
	(ख) भारत सरकार द्वारा नामजद किया हुआ उत्पादकों का प्रतिनिधि—खुम्बी उत्पादक संघ का प्रतिनिधि।
(ङ) व्यापार के प्रतिनिधि	व्यापार के तीन प्रतिनिधि जिनकी सिफारिश वाणिज्य मंत्रालय करेगा।
(च) उद्योग के प्रतिनिधि	फल तथा साग-सब्जी के परिरक्षण उद्योग के तीन प्रतिनिधि।
(छ) मजदूरों के प्रतिनिधि	(1) फार्मों में काम करने वाला—एक
	(2) कारखानों में काम करने वाला—एक
(ज) ऐसे अतिरिक्त व्यक्ति जिन्हें भारत सरकार समय-समय पर नामजद करे।	
4 सदस्य सचिव	निदेशक (बागवानी), कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग), नई दिल्ली।
5 प्रेक्षक	(जो परिषद के सदस्य नहीं होंगे, किन्तु जिन्हें परिषद के विचार विमर्श में सहायता के लिये निरंतर रूप से आमंत्रित किया जायेगा)
	1 अध्यक्ष, राज्य व्यापार निगम अथवा उनका प्रतिनिधि।
	2 भारत सरकार के कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय के कृषि विपणन सलाहकार अथवा उनका प्रतिनिधि।
	3 वित्तीय सलाहकार, कृषि विभाग, कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय।
	4. अर्थ तथा सांख्यिकी सलाहकार, कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग) अथवा उनका प्रतिनिधि।

5 सचिव, राष्ट्रीय सहकारी विकास समिति, नई दिल्ली ।

6 संयुक्त आयुक्त (वाणिज्यिक फसल), कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग), नई दिल्ली ।

(6) समय-समय पर ऐसे अन्य संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह देना, जो जरूरी समझी जायें ।

3 परिषद को विशिष्ट मुद्दों पर कार्यवाही करने के लिये स्थायी समिति, तकनीकी समिति, तथा तदर्थ समिति नियुक्त करने और विशिष्ट प्रयोजनों के लिये आवश्यकतानुसार कृषि विश्वविद्यालयों व अन्य विशेष क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को सदस्य सहयोजित करने का अधिकार होगा ।

4. परिषद की फल तथा साग-सब्जियां उगाए जाने वाले क्षेत्रों और व्यापार तथा उद्योग के महत्वपूर्ण केन्द्रों पर समय समय पर बैठकें होंगी तथा परिषद भारत सरकार को सिफारिशें करेगी ।

5. परिषद तब तक कार्य करेगी, जब तक उसे सरकार के संकल्प द्वारा भंग न कर दिया जाए । अध्यक्ष तथा परिषद के अन्य गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल परिषद में उनके नामजद किए जाने की तारीख से तीन वर्ष होगा, बशर्ते कि भारत सरकार के किसी विशेष आदेश द्वारा यह अवधि घटा या बढ़ा न दी जाए ।

6 परिषद में सदस्य के रूप में नामजद किए गए संसद सदस्यों की सदस्यता उनके संसद सदस्य न रहने पर तुरन्त समाप्त हो जायेगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों में तथा भारत सरकार के मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्रिमण्डल सचिवालय, प्रधान मंत्री का कार्यालय, लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय को भेज दी जाए ।

2 यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए ।

ए० दास, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE)

New Delhi, the 19th November 1977

RESOLUTION

No. 48012/7/76-CA I—The Government of India have decided to reconstitute with effect from 1st July, 1977 the Indian Horticulture Development Council set up vide their Resolution No. 38-1/73-CA.I. dated the 5th September, 1973. The reconstituted Council will be composed as follows :—

CHAIRMAN

A Non-official to be nominated by the Government of India

VICE-CHAIRMAN

Additional Secretary to the Government of India in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Agriculture)

MEMBERS

Members of Parliament

Three members of Parliament to be nominated by the Department of Parliamentary Affairs

Representatives of State Governments

One representative from each of the following State Governments in the Department of Agriculture/Horticulture to be nominated by the respective State Governments —

(i) Assam.
(ii) Andhra Pradesh
(iii) Himachal Pradesh
(iv) Haryana.
(v) Jammu & Kashmir.
(vi) Karnataka.
(vii) Maharashtra.
(viii) Madhya Pradesh
(ix) Meghalaya.
(x) Orissa
(xi) Punjab
(xii) Tamil Nadu
(xiii) Uttar Pradesh

Representatives of Central Government

(i) One representative of the Planning Commission.
(ii) One representative of the Ministry of Commerce.
(iii) One representative of the Department of Food.
(iv) Agriculture Commissioner to the Government of India or his nominee.
(v) Director General, Indian Council of Agricultural Research, New Delhi or his nominee
(vi) Director, Institute of Horticulture Research, 255, Upper Palace Orchards, Bangalore.
(vii) Director, Central Food Technological Research Institute, Mysore or his nominee.

Representatives of Growers

(a) One representative of growers to be nominated by the respective State Governments from each of the following States :—
(i) Assam
(ii) Andhra Pradesh
(iii) Gujarat
(iv) Haryana
(v) Himachal Pradesh
(vi) Jammu & Kashmir.
(vii) Karnataka.
(viii) Maharashtra
(ix) Meghalaya
(x) Punjab
(xi) Rajasthan
(xii) Tamil Nadu
(xiii) Uttar Pradesh
(xiv) West Bengal

(b) Growers' representative nominated by Government of India—Representative of Mushroom Growers' Association.

Representatives of Trade

Three representatives of trade to be recommended by the Ministry of Commerce.

Representatives of Industry

Three representatives of Fruit and Vegetable Processing Industry.

Representatives of Workers.

(i) engaged in farms—one.
(ii) engaged in factories.—one.

Such additional persons as may, from time to time, be nominated by the Government of India

Member Secretary

The Director (Horticulture), Ministry of Agriculture & Irrigation (Department of Agriculture), New Delhi.

OBSERVERS

(who would not be members of the Council but would be invariably invited to assist the Council in its deliberations).

1. Chairman, State Trading Corporation or his representative.
2. Agricultural Marketing Adviser—Government of India, Ministry of Agriculture & Irrigation or his representative.
3. Financial Adviser, Department of Agriculture, Ministry of Agriculture & Irrigation.
4. Economics and Statistical Adviser, Ministry of Agriculture & Irrigation (Department of Agriculture) or his representative.
5. Secretary, National Cooperative Development Corporation, New Delhi.
6. Joint Commissioner (Commercial Crops), Ministry of Agriculture & Irrigation (Department of Agriculture), New Delhi.
7. Managing Director, National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd, New Delhi.
8. Project Coordinator (Fruits), I.C.A.R, New Delhi.
9. Project Coordinator (Vegetables), I.C.A.R., New Delhi.
10. Project Coordinator (Floriculture), I.C.A.R, New Delhi.
11. Director, Mushroom Research Laboratory, H.P. Agricultural University, Solan or his representative.
12. Representative of Railways.

2. The Council will be an advisory body and will have the following functions :—

(i) to consider the development programmes in the Central and State Sectors in respect of Fruits and Vegetables (including Mushroom), review progress thereof from time to time and recommend measures for increasing the producion of Fruits and Vegetables,

(ii) to consider problems relating to the production and marketing of Fruits and Vegetables and remunerative prices to Fruit and Vegetable growers and advise Government in these matters,

(iii) to consider demands for Fruits and Vegetables in the domestic as well as export markets and advise Government about necessary arrangements for meeting the said demands through suitable development programmes,

(iv) to consider the special needs of small and marginal farmers in respect of Fruits and Vegetable production and suggest suitable measures for meeting the same,

(v) to facilitate coordination between research and development programmes relating to fruits and vegetables and to advise about the needs for improvement in the quality and productivity of fruits and vegetables; and

(vi) to advise Government on such other connected matters as may be considered necessary from time to time

3. The Council will have powers to set up Standing Committee, Technical Committee and *Ad-hoc* Committee to look into specific issues and to co-opt members such as representatives of Agricultural Universities and other special interests as and when necessary for specific purposes

4 The Council will meet periodically in areas in which fruits and vegetables are grown and at important centres of trade and industry and will make recommendations to the Government of India

5. The Council will continue to function until it is abolished by a Resolution of the Government The term of the Chairman and other non-official members of the Council would be three years from the date they are nominated on the Council unless this period is curtailed or extended by a specific order of the Government of India

6. Those members of the Council who are nominated from among Members of the Parliament will cease to be the members of the Council as soon as they cease to be Members of Parliament

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administrations of Union Territories and Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats

2. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information

A DAS
Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977